

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1097
02.12.2024 को उत्तर के लिए

अमृत धरोहर पहल

1097. श्रीमती दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अमृत धरोहर पहल के विशिष्ट उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं, जिनमें अपेक्षित पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक परिणाम भी शामिल हैं;
- (ख) अमृत धरोहर पहल के अंतर्गत इसकी शुरुआत से लेकर अब तक, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश राज्य में हुई प्रगति और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन पर अमृत धरोहर पहल का क्या प्रभाव पड़ा है और क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) उक्त पहल के कार्यान्वयन एवं सफलता में स्थानीय समुदायों एवं हितधारकों को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री;
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी), भारत सरकार की अमृत धरोहर पहल को रामसर स्थलों के विशिष्ट संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में शुरू किया गया था। इसके मुख्य घटक - प्रजाति एवं पर्यावास संरक्षण, प्रकृति पर्यटन, आर्द्रभूमि आजीविका और आर्द्रभूमि कार्बन मूल्यांकन हैं। अमृत धरोहर के अपेक्षित परिणामों में विशिष्ट संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत मूल्यों की रक्षा और संवर्धन, प्रकृति पर्यटन के अवसर पैदा करना और स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन, आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी संतुलन के रख-रखाव को सुनिश्चित करते हुए इनके इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करना, जैव विविधता और कार्बन स्टॉक की सुरक्षा और वृद्धि करना शामिल है।

(ख) से (घ) आंध्र प्रदेश राज्य सहित अमृत धरोहर पहल के अंतर्गत हुई प्रगति, प्रमुख घटकों के अंतर्गत किए गए अध्ययन तथा स्थानीय समुदायों और हितधारकों की भागीदारी का विवरण निम्नानुसार है:

(i) **प्रजातियाँ एवं पर्यावास संरक्षण:** भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा क्रमशः 75 रामसर स्थलों की वनस्पतियों और जीव-जंतुओं की सूची तैयार करने के लिए अध्ययन किए गए हैं। रामसर स्थलों के लिए जन जैव विविधता रजिस्टर (पीबीआर) बनाए/अद्यतन किए आंध्र प्रदेश में रामसर स्थल कोलेरु झील के लिए 73 पीबीआर बनाए/अद्यतन किए गए हैं। प्रबंधन योजनाओं की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय आर्द्रभूमि के लिए प्रबंधन प्रभावशीलता ट्रेकिंग टूल (एमईटीटी) संबंधी दिशानिर्देश प्रकाशित किए गए और अब तक 22 रामसर स्थलों के लिए एमईटीटी आकलन किया जा चुका है। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से स्कूली छात्रों के विभिन्न स्तरों के लिए आर्द्रभूमि पर दस शैक्षिक वीडियो बनाए गए हैं। आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए कार्यान्वयन की रूपरेखा जारी की गई है।

(ii) **प्रकृति पर्यटन एवं आर्द्रभूमि आजीविका:** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस मामले का अध्ययन करने तथा प्रकृति पर्यटन एवं आर्द्रभूमि आजीविका पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने हेतु पर्यटन मंत्रालय के साथ सहयोग किया है। पांच रामसर स्थलों के 196 स्थानीय समुदायों के सदस्यों के लिए वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम और पर्यावरण नाविक प्रमाणन संबंधी प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे। इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के हरित कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रकृति गाइडों के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया है।

(iii) **आर्द्रभूमि कार्बन मूल्यांकन:** 'आर्द्रभूमियों में कार्बन स्टॉक के आकलन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया' जारी की गई, जिसका उपयोग आंध्र प्रदेश में कोलेरु झील सहित 39 रामसर स्थलों के कार्बन स्टॉक का आकलन करने के लिए किया गया है।
